आरक्षित निर्णय

रिपोर्टेबल

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

आपराधिक विविध आवेदन संख्या 167/2016

चेतन बलुटिया

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

उपस्थित :- श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री हेमंत सिंह मेहरा के साथ श्री एस एस अधिकारी, अधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य के लिए श्री हर्षित सांवाल, अधिवक्ता, श्री आर. एस. सम्मल संक्षिप्त विवरण रखते हुए प्रतिवादी नंबर. 2 के लिए अधिवक्ता।

माननीय रवींद्र मैथानी, न्यायमूर्ति

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 (संक्षेप में 'संहिता') के तहत यह याचिका आपराधिक संशोधन संख्या 74/2013, चेतन बलूटिया बनाम राज्य और अन्य, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, हल्द्वानी, जिला नैनीताल की अदालत द्वारा (संक्षेप में 'पुनरीक्षण') में 26.09.2015 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है। ।

2. विवादित आदेश द्वारा, सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया द्वारा दायर खंड 31-बी के तहत एक आवेदन को अनुमति देते हुए, उन्हें आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

3. विवाद को तय करने के लिए आवश्यक तथ्य, संक्षेप में बताए गए, नीचे दिए गए हैं

प्रतिवादी नं.2 ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (संक्षेप में 'अधिनियम') और याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुख्तारनामा धारक पंकज कापड़ी के माध्यम द्वारा भा.दं.सं. की धारा 420 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर आपराधिक मामला सं. 1059/2013, कैलाश चंद्र बलूटिया बनाम चेतन बलूटिया की स्थापना विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी (संक्षेप में 'मामला') की अदालत में की गई थी।

05.03.2013 को जांच पश्चात याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 138 के तहत तलब किया गया था। यह याचिकाकर्ता को तलब करने का आदेश है, जिसे उसने पुनरीक्षण में चुनौती दी थी।संशोधन विचाराधीन रहने के दौरान, सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया द्वारा खंड 31-बी के से प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उनके पति कैलाश चंद्र बलूटिया की मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया द्वारा दायर आवेदन पर आपत्ति दर्ज की। आपत्तियों के अनुसार, स्वर्गीय श्री.कैलाश चंद्र बलूटिया ने दिनांक 30.09.2013 को एक वसीयत निष्पादित करके सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया को अपनी सम्पति से अलग कर दिया था।इसलिए सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया को अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकी।यह भी आपत्ति जताई गई थी कि स्वर्गीय श्रीकैलाश चंद्र बलूटिया चेक के धारक थे, परन्तु उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात उनमें निहित कानूनी अधिकार समाप्त हो गया और उनके द्वारा उनकी पत्नी सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया को चेक के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया।

4. पक्षकारों को सुनने पश्चात, विवादित आदेश द्वारा, विद्वान निचली अदालत ने सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया द्वारा धारा 31-बी के तहत आवेदन को अनुमति दी और उन्हें अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी। यह आदेश विवादित है।

5. पक्षकारों के विद्वत वकील को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया ।

6. याचिकाकर्ता के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में निम्नलिखित बिंदु उठाएः

(1) सुश्री मार्गिट गुनीला बलूटिया को स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र बलुटिया द्वारा पहले ही सभी चल और अचल सम्पति से वंचित कर दिया गया था।कैलाश चंद्र बलूतिया। अश्विन नानुभाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 983 के मामले में निर्णय, तत्काल मामले में लागू नहीं है क्योंकि तत्काल एक समन

मामला है और वे सिद्धांत जो वारंट विचारण से संबंधित अश्विन (सुप्रा) के मामले में निर्धारित किए गए थे।

(2) मात्र एक व्यक्ति जिसे अभियोजन जारी रखने का अधिकार है, वह प्रतिस्थापन की मांग कर सकता है।एल. आर. एस., (2004) 12 एस. सी. सी. 509 द्वारा जिमी जहांगीर मदन बनाम बॉली करियप्पा हिंडले (मृत) के मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया है।

(3) अधिनियम खंड धारा 138 के तहत अपराध अनिवार्य रूप से मृतक खंड चल सम्पति के विरुद्ध एक अपराध है और यह व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं है, इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिस्थापन आवेदन एक व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है जिसे मृतक द्वारा सम्पति से विभाजित किया गया है।प्रतिस्थापन आवेदन चूंकि मामले में दायर नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह के आवेदन को संशोधन में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7. प्रतिवादी की ओर से नं.2, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि पुनरीक्षण में, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को इसे संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।इसके अलावा, सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र बलूटिया की पत्नी हैं।समन मामले में भी, अदालत किसी व्यक्ति को अभियोजन जारी रखने की अनुमति दे सकती है।यदि प्रतिस्थापन की अनुमति दी जाती है और मृतक की पत्नी को अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह किसी को भी पूर्वाग्रहित नहीं करता है; सुश्री मार्गिट गुनीला बलूटिया को दिवंगत श्री कैलाश चंद्र बलूटिया द्वारा सम्पति से विभाजित नहीं किया गया था।इसके बजाय, यह स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र बलूटिया की पत्नी ने खुद को स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र बलूटिया सम्पति से दूर कर लिया।प्रश्नगत चेक स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र बलूटिया द्वारा जारी वसीयत में शामिल नहीं था। कैलाश चंद्र बलूतिया।विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि विवादित आदेश कानून की नजर में मान्य है और कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

8. शुरुआत में, जब तर्क शुरू हुआ, तो न्यायालय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता से जानना चाहती थी कि संशोधन में प्रतिस्थापन की क्या आवश्यकता थी।ऐसा इसलिए है क्योंकि एक

बार स्वीकार किए जाने के बाद, संशोधन का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाता है और इस संबंध में किसी भी पक्ष की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि प्रणब कुमार मित्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य, एआईआर 1959 एस. सी. 144 के मामले में हुआ था।

प्रतिवादी नं.2 /बोर्ड के विद्वत वकील 2 इसे प्रस्तुत करेगा कि यदि प्रतिस्थापन किया जाता है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

9. प्रणब कुमार (सुप्रा) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि "चाहे वह एक अभियुक्त व्यक्ति हो या वह एक शिकायतकर्ता हो जिसने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का रुख किया है, यदि उच्च न्यायालय ने एक नियम जारी किया है, तो उस नियम अन्य बातों के साथ साथ सुनवाई और निर्धारण कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, चाहे उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता जीवित हो या मृत, या क्या उसका प्रतिनिधित्व अदालत में एक कानूनी व्यवसायी द्वारा किया जाता है। (पैरा 6)

10. तत्काल मामले में, भले ही स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र बलूटिया की मृत्यु हो चुकी है, ने संशोधन को जारी रखना बंद नहीं किया होगा, लेकिन साथ ही, अगर किसी व्यक्ति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता।प्रश्न यह है कि क्या उस व्यक्ति को अभियोजन जारी रखने की अनुमति दी गई है? उस सीमा तक, विवाद अब हल हो जाएगा।संहिता की खंड 302 किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन जारी रखने की अनुमति देती है।यह निम्न रूप में इस प्रकार परिभाषित है -

> **302. अभियोजन चलाने की अनुमति** - (1) किसी मामले की जाँच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन

महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगाः

बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

(2) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या एक वकील द्वारा ऐसा कर सकता है।

11. तत्काल मामला अधिनियम खंड धारा 138 के से कार्यवाही से उत्पन्न होता है। यह समन का मामला है।निस्संदेह संहिता खंड धारा 256 के से, शिकायतकर्ता खंड गैर-उपस्थिति में, अभियुक्त को तब तक बरी किया जा सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट किसी अन्य दिन के लिए सुनवाई स्थगित करना उचित न समझे।संहिता की धारा 256 का खंड और अधिक विस्तृत बनाता है कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में में भी मामले की सुनवाई कैसे की जा सकती है? संहिता का खंड 256 इस प्रकार हैः

"256. शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति या मृत्यु -

(1).....

बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किसी वादी द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की मत है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और मामले के साथ आगे बढ़ सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है।"

12. एक तर्क दिया गया है कि अश्विन (सुप्रा) के मामले में, वारंट विचारण में सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, इसलिए, वे तत्काल मामले में आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि यह एक समन मामला है और शिकायतकर्ता की मृत्यु के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दोषमुक्ति दिया जाएगा।

13. इस तर्क में इस सरल कारण के लिए कोई सार नहीं है कि संहिता की खंड 302 समन मामले और वारंट मामले के बीच अंतर नहीं करती है। इसके अलावा, संहिता की खंड 256 के से, शिकायतकर्ता की मृत्यु पर भी, यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी को बरी किया जा सके। शिकायतकर्ता की मृत्यु के बावजूद न्यायालय अभी भी अभियोजन जारी रखेगा। बालासाहेब के. ठाकरे और एक अन्य बनाम वेंकट @ बबलू और एक अन्य, (2006) 5 एससीसी 530 (फैसले के पैराग्राफ 3) के मामले में इसी तरह की दलीलें दी गईं।लेकिन इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया।बालासाहेब के. ठाकरे (सुप्रा) के मामले में न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह यह था कि "संहिता की धारा 302 का आवेदन लाने के लिए, अभियोजन चलाने की अनुमति मामले की जांच या सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट खंड प्राप्त करनी होती है।" (पैराग्राफ 6)

14. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन मात्र उस व्यक्ति द्वारा जारी रखा जा सकता है जिसे "जारी रखने का अधिकार" है और जिमी जहांगीर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया है।इसका परिच्छेद 9 इस प्रकार हैः

> "9. संहिता की धारा 205 और 302 की भाषा समान है।संहिता की धारा 302 के तहत, एक पक्ष अभियोजन जारी रखने से लिए स्वयं आवेदन कर सकता है या इखंड एक वकील द्वारा किया जा सकता है।जैसा कि संहिता की धारा 2 (क्यू) के तहत प्रदान किया गया है, अभियोजन जारी रखने का अनुरोध या तो कानूनी रूप खंड योग्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जो अधिवक्ता अधिनियम के से अदालत में वकालत करने के लिए अधिकृत है; या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप खंड एक मुख्तारनामा धारक शामिल होगा, जिसमें ऐसी अनुमति अदालत द्वारा दी जा सकती है, जहां अभियोजन मात्र तभी लंबित है जब यह उस व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है जो अभियोजन जारी रखने का हकदार है, न कि मुख्तारनामा धारक द्वारा।संहिता की धारा 205 के तहत, एक आरोपी को व्यक्तिगत रूप खंड उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है और उखंड एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है।इसी तरह, संहिता की धारा 302 के से, एक व्यक्ति, जो अभियोजन जारी रखने का हकदार है, द्वारा स्वयं

आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उपरोक्त दोनों प्रावधानों के से, व्यक्तिगत रूप द्वारा कदम उठाने के बजाय, एक पक्ष का प्रतिनिधित्व एक वकील के माध्यम द्वारा किया जा सकता है।एटोमी धारक की शक्ति संहिता के दोनों प्रावधानों के तहत संबंधित पक्ष का अभ्यावेदन कर सकती है, यदि इस तरह के अभ्यावेदन के लिए अदालत तहत गर्भ धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुमति मांगी जाती है और उसके द्वारा दी जाती है। लेकिन जहां संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी जाती है, जिसका अर्थ है कि संहिता की धारा 205 के मामले में एक अभियुक्त और संहिता की धारा 302 के मामले में एक पक्ष जिखंड अभियोजन जारी रखने का अधिकार है, अटमी धारक की शक्ति को कार्यवाही में गर्भ धारण करने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

(महत्व दिया गया)

15. अश्विन (सुप्रा) के मामले में, एक तर्क दिया गया था कि यदि न्यायालय यह प्रावधान करता है कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की शिकायत पर संज्ञान लिया जा सकता है, तो कार्यवाही की निरंतरता भी उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।यह तर्क दिया गया था कि "यदि संज्ञान तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि धारा में दिए गए तरीके से शिकायत नहीं खंड गई थी, तो न्यायालय तब तक जांच के साथ आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वही शर्त मौजूद न रहे।इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया।माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "यह खंड एक बाधा उत्पन्न करती है जिसे संज्ञान लेने से पहले हटा दिया जाना चाहिए।एक बार बार को हटा दिए जाने के बाद, क्योंकि उचित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज खंड है, धारा अपने आप काम करती है।यदि कोई अन्य प्रतिबंध भी था, तो संहिता ने ऐसा कहा होगा।ऐसा नहीं कहने के बाद, किसी को खंड को पूरा माना जाना चाहिए और काम करना चाहिए।" (पैरा 7)

16. यह सच है कि जिमी जहांगीर (सुप्रा) के मामले में, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 302 से, एक पक्ष जिसे अभियोजन जारी रखने का अधिकार है, वह अभियोजन जारी रखने की अनुमति ले सकता है न कि अटॉर्नी धारक की शक्ति। जिमी जहांगीर (सुप्रा) के मामले में प्रश्न यह था कि क्या अटॉर्नी धारक की शक्ति को शिकायतकर्ता के

उत्तराधिकारियों का वादी माना जा सकता है? (पैराग्राफ 5 अंतिम पंक्तियाँ) और उस संदर्भ में, टिप्पणियाँ ऊपर पैराग्राफ 9 में उद्धृत की गई हैं।

17. संहिता की खंड 302 में यह नहीं कहा गया है कि मात्र मृतक के कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी ही अभियोजन जारी रख सकते हैं।संहिता की खंड 302 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को संहिता द्वारा खंड में दी गई सीमा के अधीन अभियोजन चलाने की अनुमति दी जा सकती है।"कोई भी व्यक्ति" शब्द महत्वपूर्ण हैं।यह सच है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध व्यक्ति विशिष्ट है और यह सम्पति खंड संबंधित है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का सम्पति पर कोई अधिकार नहीं है, उखंड अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी सत्य है कि अधिनियम की धारा 138 के अधीन संज्ञान, मात्र किसी प्राप्तकर्ता द्वारा लिखित शिकायत पर लिया जा सकता है, या जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा अधिनियम की धारा 142 के तहत प्रदान किए गए चेक के नियत समय में, लेकिन, यदि अधिनियम की धारा 142 को संहिता की धारा 256 और धारा 302 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के पश्चात अभियोजन एक ऐखंड व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाना चाहिए जिसका मृतक की सम्पति में हित है या जो मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी है।

18. यह तर्क दिया जाता है कि मृतक कैलाश चंद्र बलूटिया ने सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया को अपनी सम्पति से अलग कर दिया था।इस संबंध में एक वसीयत भेजी गई है।यह सच है कि वसीयत की प्रति के अनुसार, सुश्री मार्गिट गुनीला बलूटिया को भारत में किसी भी चल या अचल सम्पति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है क्योंकि वसीयत के अनुसार, सुश्री मार्गिट गुनीला बलूटिया, जो स्वीडिश नागरिक हैं, को ऐसी सम्पति में कोई दिलचस्पी नहीं थी।इसके अलावा, प्रश्नगत चेक वसीयत का हिस्सा नहीं है।इसलिए, मृतक कैलाश चंद्र बलूटिया की

वसीयत के बल पर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया अभियोजन का संचालन नहीं कर सकती हैं।

19. याचिकाकर्ता के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करेंगे कि चूंकि मामले में प्रतिस्थापन नहीं किया गया है, इसलिए संशोधन में प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस तर्क का कोई बल नहीं है।संशोधन संबंधित समय पर चल रहा था और प्रतिस्थापन किया गया था।जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, मामले को जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।

20. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि न्यायालय संहिता की खंड 302 के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की खंड 138 के तहत अभियोजन जारी रखने की अनुमति दे सकता है, जो संहिता की खंड 302 के तहत दी गई सीमाओं के अधीन है।तत्काल मामले में, सुश्री मार्गित गुनीला बलूटिया मृतक कैलाश चंद्र बलूटिया की पत्नी हैं।उसे हर रात अभियोजन जारी रखना है और इस न्यायालय का विचार है कि निचली अदालत ने सुश्री मार्गिट गुनीला बलूटिया के आवेदन 31 (बी) को अभियोजन जारी रखने की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है।याचिका में कोई सार नहीं है।

21. याचिका खारिज की जाती है।

(रवींद्र मैठानी, जे)
05.06.2020

उज्जवल